(1435/SAN/RPS)

1435 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-five minutes past Fourteen of the Clock.

(Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377- LAID

1436 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

1437 hours

(*At this stage, Dr. G. Ranjith Reddy and some other hon. Members came and sat near the Table.*)

… (*Interruptions*)

Re: Establishment of Health Care Centres in Jhansi District

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): As per the Lancet Oncology study, India reports about 1.3 million cancer cases annually and almost eight per cent of total deaths. This is likely to increase in the next 5-to-10 years due to delay in diagnosis and treatment owing to the pandemic. Similarly, there is also an increase in the cases of Heart disease.

Jhansi has five assembly segments which are mostly populated by backward-class people. Most of the patients with cancer and heart disease in the district find it difficult to get the treatment. They need to travel to Lucknow or Delhi to get their treatment done. The care of non-communicable diseases is dependent on the stage of diagnosis, and any disruption will impact treatment and survival. Therefore, I would like to request the Health Minister to take necessary steps to establish healthcare centres which will help Cancer and Heart disease patients to get treatment in Jhansi district.

(ends)

Re: Need to accord the status of full-fledged railway station to Sadisopur Railway Station in Pataliputra parliamentary constituency, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): हमारे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के मनेर विधानसभा,बिहटा प्रखंड के सादिसोपुर रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिए जाने की महोदय के माध्यम से मांग करता हूँ मेरी इस मांग के निम्न कारण हैं :-

1. सादिसोपुर रेलवे स्टेशन बिहटा हवाई अड्डा (निर्माणाधीन)का निकटतम रेलवे स्टेशन है,
2. सादिसोपुर से आईआईटी संस्थान बिहटा की दूरी मात्र 6 km है.
3. सादिसोपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 40 गाँव के लोग प्रतिदिन सफर करते है.
4. रेलवे स्टेशन से दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता एवं दैनिक मजदूरों का बिहार की राजधानी पटना से व्यापार हेतु यातायत का मुख्य साधन रेल है.
5. बिहार की राजधानी एवं अन्य सरकारी प्राइवेट चिकित्सा के लिए लोग रेल का उपयोग करते है.

सादिसोपुर रेलवे स्टेशन से AIIMS की दूरी लगभग 12 km है। स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा मिल जाने से आम जनों को बहुत ही सुविधा मिल सकेगी। अतः महोदय से अनुरोध है इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने की कृपा की जाए। धन्यवाद

(इति)

Re: Need to restore railway services discontinued during Covid-19 Pandemic in Wardha parliamentary constituency, Maharashtra.

श्री रामदास तडस (वर्धा): सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि कोविड-19 महामारी के दरम्यान रेल मंत्रालय के माध्यम से रेल सेवा में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए थे।

रेल एक्सप्रेस मेल गाड़ियों के अनेक स्टॉपेज रद्द किए गए थे, अनेक रेल गाड़ियाँ रद्द हैं। की गई थी। वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाला कंसेसन विशेष ट्रेन सेवा में बंद किया गया है। इन सभी कारणों से प्रवासी वर्ग में रोष बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान में कोविड टीकाकरण मुहिम तेज गति से प्रगति पर है। हवाई सेवा एवं रोड ट्रांसपोर्ट सेवा भी सामान्य हो गई है। ऐसी स्थिति में रेल सेवा सामान्य करने हेतु आम जनता भारी मांग कर रही है।

आपके माध्यम से मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि कोविड के पूर्व जो रेल सेवाएँ उपलब्ध थीं, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनःश्च प्रारंभ करने के संदर्भ में उचित निर्णय लेने की कृपा करे।

(इति)

Re: Need to expedite Ara-Kochas-Bhabua Road and Bhabua Road to Maa Mundeshwari Dham railway line projects in Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): आरा-कोचस-भभुआ रोड तथा भभुआ रोड से मां मुण्डेश्वरी धाम तक रेल पथ का बजटीय प्रावधान वर्ष 2014-15 में किया गया हैं, परंतु उक्त योजना के निर्माण में विलंब होने से आदिवासी बाहुल्य इलाका आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत 'माता मुंडेश्वरी धाम' तेलहार कुण्ड, हरशुब्रम्ह, जगदहवॉ बांध इत्यादि भी पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। अत: इस योजना का शीघ्र निर्माण करने हेतु रेल मंत्रालय को सदन के माध्यम से निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Providing Connectivity under PMGSY to Habitations having a Population of 100+ in Nandurbar Parliamentary Constituency

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): PMGSY provides that habitations with a population of 250+ in plain areas and 100+ in North-Eastern and Himalayan states, Desert areas, Tribal (Schedule V) areas and 100+ for selected tribal and backward districts as identified by the Ministry of Home Affairs as per Census, 2001 were to be covered under the scheme. My constituency of Nandurbar is a Schedule V area with low human development index & high malnutrition cases & has been declared as an aspirational district with a major tribal population along with hilly terrain. Residents are under extreme distress because they are unable to travel for treatment and medical aid due to poor maintenance and connectivity of roads. I request the Government to provide connectivity under PMGSY to habitations having a population of 100+ in Nandurbar to ensure ease of travelling to residents of these unconnected habitations which are not covered under PMGSY at the earliest to speed up development

(ends)

Re: Need to upgrade Post Office Passport Sewa Kendra, Ajmer, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अजमेर संभाग मुख्यालय पर संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर 4 मार्च 2018 से निरन्तर आमजन को अपनी सेवायें दे रहा है। यहॉ पर वर्तमान में अजमेर संभाग के चारों जिला यथा अजमेर-भीलवाडा-नागौर-टोंक के साथ-साथ पाली एवं राजसमंद संसदीय़ क्षैत्र के व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, उच्चशिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ-साथ आमजन को पासपोर्ट सबंधी सेवाओं का आंशिक लाभ ही मिल रहा है, लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए उक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर में तत्काल पासपोर्ट, पीसीसी की सुविधा, सत्यापित करने वाले सक्षम अधिकारी के अभाव आदि के साथ-साथ अन्य विभागीय सेवाओं का समग्र लाभ उक्त भी वांछित वर्गो को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान मे राजस्थान प्रदेश में रीजनल पासपोर्ट अधिकारी जयपुर के अधीन चार स्थानो पर यथा- जयपुर-जोधपुर-उदयपुर एवं सीकर में ही पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र संचालित है और अजमेर में संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवाकेन्द्र का कार्यभार प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों पर संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र से अधिक है। अतः अजमेर (राजस्थान) संभाग मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर को आगामी विभागीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र में क्रमोन्नत कराने की सक्षम विभागीय स्वीकृती जारी कराकर मुझे अनुग्रहित करावें, ताकि अजमेर-भीलवाड़ा-नागौर-टोंक-पाली-राजसमंदआदि संसदीय क्षेत्रों के वाशिंदों को उक्त पूर्ण पासपोर्ट सेवा केन्द्र अजमेर का समुचित लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Inclusion of Balurghat Railway Station under Station Redevelopment Project

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): I raise the demand to include the Balurghat Railway Station under Station Redevelopment Project and develop Balurghat Railway Station with infrastructure facilities including drinking water, passenger shed, display board, construction of separate toilet for women, air-conditioned waiting room and hotel. The Buniadpur Railway station has only one railway platform which creates problem to passengers while boarding/deboarding at the railway platform. Therefore, I request the Ministry of Railways to sanction the construction of at least 3 new platforms with permanent shades equipped with all other basic public amenities/facilities at the Buniadpur Railway station.

(ends)

Re: Need to increase salary of vocational trainers employed in government schools in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 2015 से दिल्ली के 334 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 725 वोकेशनल ट्रेनरों को उचित वेतन न मिलने के कारण वोकेशनल ट्रेनरों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। Skill Development के अंतर्गत ये शिक्षक स्कूलों में IT (Information and Technology), Beauty and Wellness, Travel and Tourism, Banking and Financial Services, Electrical Technology, Physical Education, Retail, Healthcare 31 Security Trade में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हजारों बच्चों को इनकी वजह से बडी बडी MNC Companies में नौकरी मिली हैं। दिल्ली सरकार इन विषयों से होने वाले लाभ का जिक्र तो हमेशा करती है, परन्तु इन शिक्षकों को सही वेतन नहीं देती है और एक तरह से उनका शोषण कर रही है। वोकेशनल ट्रेनरों की सैलरी 2015 में बीस हजार रुपये निर्धारित हुई थी, जो कि अभी तक 6 साल से स्थिर बनी हुई है। परन्तु हकीकत में उनको मात्र सोलह हजार रुपए के लगभग सैलरी मिलती है। आज के समय में जो unskilled Worker के न्यूनतम वेतन के समान भी नहीं हैं। वोकेशनल ट्रेनरों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस विषय में कई बार ज्ञापन दिया पर किसी ने भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया है। कॉन्ट्रेक्ट एजेंसियों के माध्यम से जैसे अभी कछ लोग आढतियों से पैसा खाकर किसानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही उसी पैटर्न पर बिचौलियों के द्वारा वेतन देते हैं सोलह हजार और चार हजार रुपए बीच में ही खा जाते हैं। हर साल लगभग ढाई से तीन करोड़ रूपए का घोटाला हो रहा है। केजरीवाल द्वारा अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट देकर उनका शोषण किया जा रहा है। माननीय उप राज्यपाल महोदय इस मामले में संज्ञान लें और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। परमानेंट कर्मचारियों को बोनस मिलता है, इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। इनको सभी सुविधाओं से अलग रखा गया है और इनका शोषण किया जा रहा है। आने वाले समय में ये इस लायक भी नहीं रहेंगे कि कहीं सरकारी या अच्छी जगह नौकरी कर सकें। इनके जीवन को लटकाया जा रहा है। महोदय, आपके माध्यम से संवेदनहीन दिल्ली के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वोकेशनल ट्रेनरों की सैलरी को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए जिससे वो भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके।

(इति)

Re: Need to reform the judicial system

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मैं सदन का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2021 में कर्नाटक राज्य बार काउंसिल, बैंगलुरू द्वारा दिवंगत न्यायमूर्ति एम.एम. शांतनगौडर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस उद्बोधन की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था मूल रूप से औपनिवेशिक होने के कारण भारतीय आबादी की जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: हमारी कानून प्रणाली/कानून व्यवस्था को देश के मुताबिक बदलने की जरूरत है तथा न्याय वितरण का सरलीकरण हमारा अपना स्वयं का होना चाहिए तथा न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने उद्बोधन में वैकल्पिक विवाद समाधान की जरूरत पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि वैकल्पिक विवाद समाधान संसाधनों को बचाने और कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा तथा वैकल्पिक विवाद तंत्र जैसे कि मध्यस्थता और सुलह का उपयोग पक्षों के बीच खिंचाव को कम करने में मदद करेगा एवं इससे संसाधनों की भी बचत होगी और साथ ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने में मददकारी होगा, जिससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से छुटकारा मिलेगा और समय की भी बचत होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने उपरोक्त उद्बोधन में यह भी कहा है कि आम आदमी अदालतों और अधिकारियों से संपर्क करने से डरते हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाते समय उसे डर नहीं लगना चाहिए तथा न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जज और कोर्ट के सामने सच बोलने में आम आदमी को हिचकिचाहट न हो और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी न्याय प्रणाली का केन्द्र बिंदु वादी, यानि कि न्याय चाहने वाला ही होता है तथा ग्रामीण लोग अंग्रेजी में कार्यवाही नहीं समझते हैं, वे उन तर्कों या दलीलों को भी नहीं समझते हैं जो ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी, उनके लिए एक विदेशी भाषा है। ऐसे में वे न्याय पाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तथा अदालतों को वादियों के अनुकूल होना चाहिए, ताकि वे अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सके।

इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के उपरोक्त उद्बोधन के परामर्शानुसार देशहित में आवश्यक पहल किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

(इति)

Re: Four-laning of National Highway No. 24 (Bareilley - Sitapur) in Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उ0प्र0 राज्य में बरेली-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-24 क्षेत्र का मुख्य मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण एवं 4 लेन का निर्माण कार्य विगत 11 वर्षों से चल रहा है किन्तु अभी तक यह मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 160 कि.मी. को ऐरा इन्फा इंजीनियरिंग कम्पनी के द्वारा सन् 2010 से निर्माण कार्य शुरू कर सन् 2019 में अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया तथा इस मार्ग में लगभग 100 कि.मी. सीधे भाग पर 4 लेन का कार्य पुरानी कम्पनी द्वारा किया गया। किन्तु इस मार्ग पर बनने वाले लगभग 50 पुल/फ्लाइओवर का कार्य तो शुरू नहीं किया गया था या तो अधूरा छोड़ दिया गया और शेष कार्य अथॉरिटी द्वारा नया टेण्डर करके दिसम्बर 2019 में कार्य शुरू कराया गया।

इस शेष कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण कर डी0पी0आर0 बनाने का कार्य आई०सी०टी० कम्पनी को दिया गया, लेकिन इस कम्पनी द्वारा अनुबन्ध गठन तक कोई भी डी0पी0आर0 अथॉरिटी को नहीं दिया गया ओर अथॉरिटी द्वारा बिना विस्तृत सर्वेक्षण के ही अनिश्चित मात्राओं के आधार पर अनुबंध का गठन कर दिया गया। तत्पश्चात जून 2020 में विस्तृत डी0पी0आर0 तथा अंततः नवम्बर 2020 में डी0पी0आर0 अथॉरिटी को जमा की गई। तब से आज तक अथॉरिटी के स्थलीय अधिकारियों द्वारा वेरिएशन ऑर्डर न स्वीकृत कर विभागीय लिखा पढ़ी में प्रोजेक्ट को फंसाकर रखा हुआ है।

मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि कार्यदायी संस्था की पर्याप्त मशीनरी (3 सैट ऑफ प्लान्ट एवं मशीनरी) साइट पर अनुपयोगित खड़ी है, क्योंकि कार्य स्थल के अनुसार कार्य किये जाने हेतु आवश्यक वेरिएशन ऑर्डर अथॉरिटी के स्थलीय अधिकारियों द्वारा लगभग 1.5 वर्ष से लम्बित डाल रखा है। अब अधिकारियों द्वारा इस कार्य को बांटकर लगभग रू0 200 करोड़ का नया टेण्डर करने की कूट रचना की जा रही है, परिणामस्वरूप कार्य को पूर्ण करने में और अधिक देरी होगी। लेकिन, कार्यदायी संस्था वेरिएशन ऑर्डर शीघ्र सेक्शन होने पर पूरा कार्य 6 माह में पुराने रेट पर करने के लिए तैयार है।

अतः जनहित में सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कार्यदायी संस्था से पूरा कार्य पुराने दरों पर ही कराये जाने हेतु समुचित कदम उठाएं, ताकि उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य तुरन्त पूरा हो सके।

(इति)

Re: Need to open 'Rani Ki Vav', a world heritage site at Patan, Gujarat at night also for tourists

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटण में सोलंकी युग में निर्मित रानी की वाव विश्व विरासत स्मारक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है एवम सरकार ने रानी की वाव १०० रुपये के नोट पर अंकित कर के विश्व को इस की पहचान करवाई हैं. इस स्मारक को देखने के लिए हर रोज देश-विदेश से सैकड़ों पर्यटक और मुलाकाती आते है। यह वाव पर्यटकों के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खुली रहती है। अगर स्मारक पर रात्रि के समय रोशनी की जाये और वाव को रात्रि में पर्यटको के लिए खुला रखा जाए तो मुलाकातियों की संख्या में काफी बढोतरी होने से पर्यटन स्थल की ख्याति के साथ स्थानीय लोगो को रोजी रोटी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत में कई स्मारकों को देर रात्रि तक पर्यटकों के लिए खुला रखा जाता है। यह सुविधा रानी की वाव के लिये उपलब्ध होना आवश्यक हैं।

आप के माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से मेरा आग्रहपूर्ण अनुरोध हैं कि इस प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को निर्देश देने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Speedy Completion of Remaining work Pertaining to NH-19.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I would like to draw your attention towards the physical progress of the NH-19. 87% has been completed that is 49.31 km out of 66.74 km length. Although the work on construction of the NH had begun a decade back, it could not be completed due to shortage of funds, court cases and protests by contractors. However, it has now been revived. On 30th October, 2021, a proposal for an additional fund of Rs. 191 crore was sent to NHAI for approval of competent authority. There has been an inordinate delay in the completion of its construction. I request the National Highways Authority of India, Ministry of Road Transport and Highways to take cognisance of the matter and direct speedy completion of the project.

(ends)

Re: Need to constitute a committee at district level for monitoring implementation of Jal Jeevan Mission scheme

श्री राहुल कस्वां (चुरू): जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना हैं जिसके तहत 2024 तक देश की अधिकतर आबादी तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुँचाने का भारत सरकार का उद्देश्य हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में उक्त कार्य अपनी पूर्ण गति से चल रहा हैं | लेकिन पिछले काफी दिन से पूरे राजस्थान भर से इस योजना में अनियमित्तताओं की अनेक शिकायतें लगातार आ रही हैं | राजस्थान में काफी स्थानों पर कार्य की गुणवत्ता और क्रियान्वन में काफी कोताही बरती जा रही हैं जिसकी वजह से इतनी महत्वपूर्ण योजना को काफी नुकसान हो रहा हैं | इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के गाँवों में तो कनेक्शन किये जा रहे हैं लेकिन वहां पर काफी आबादी खेतों में ढाणियों में भी निवास करती हैं, लेकिन उन्हें इस योजना से नहीं जोड़ा जा रहा हैं | जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र का आम आदमी इस बेहतरीन योजना से वंचित रह रहा हैं |

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि जिला स्तर पर स्थानीय संसद सदस्य की निगरानी में एक समिति का गठन किया जाये ताकि इस बेहतरीन योजना का बेहतरीन क्रियान्वन गुणवतापूर्ण और समय पर करवाया जा सकें और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर तक नल पहुँचाया जाये ताकि ढाणियों मे बसे नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिल सकें |

(इति)

Re: Upgradation of Thiruparankundram Railway Station in Madurai District

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I would like to urge the Government to announce Thiruparankundram Railway Station in Madurai District, Tamilnadu as the junction and take appropriate action to upgrade this station with all facilities. Thiruprankundram is one of the busiest stations since majority of trains running towards southern districts like Thirunelveli, Tutocurin, Thiruchendur, Senkottai, Nagarkoil, Kanniyakumar, Thiruvananthapuram and Quilom are crossing this station. At the same time, trains from these southern districts are being operated through this station to various destinations of other states including Bengaluru, Mumbai, Mysuru etc. Under the circumstances, in case of expansion of Madurai Airport and functioning of upcoming All India Institute of Medical Science, this station would become more congested since the number of passengers would be manifold in future.

Therefore, I would like to urge the Government to upgrade this station as the Junction and take necessary action for its development with enhanced passenger facilities. (ends)

Re: Alleged Exorbitant Rate in Conduct of COVID-19 Antigen Tests at the Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad, Hyderabad

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to bring to your kind notice the fact regarding Antigen tests for Covid-19 being conducted at high rates at the Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad, Hyderabad.

It is stated that some private organisations are conducting Antigen tests on a compulsory basis for the passengers who are leaving for abroad from the RGI Airport which has become costly with exorbitant collection of fee of Rs. 4,500/- for each test from each passenger just before the departure of flight despite the passengers having reports of negative RTPCR which they have taken 72 hours before their departure. In this regard, many passengers have brought this matter to the notice of the undersigned to take up this issue to do justice in the matter.

Therefore, I request the Hon'ble Minister of Civil Aviation, to kindly intervene in the matter and do the needful

(ends)

Re: Declaration of wild boars a vermin

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The issue of problematic wild boar is very serious in the state of Kerala. A request was submitted to the central government to declare the animal as a vermin on 01/11/2020, in exercise of the powers conferred by Section 62 of the wildlife protection act, 1972. However, this was returned by the centre, directing the state to use Section 11(1)(b) of Wildlife Protection Act, 1972 utilising the services of Panchayati Raj Institutions. However, the state has been utilising Section 11(1)(b) since 2011 and it has been found ineffective in curbing the issue. The crop loss and other risks posed by the Wild Boar is causing a great toll on the lives of people who live close to the forests. I urge the government to take immediate decision and declare the wild boar to be a vermin under Section 62 of WPA, 1972.

(ends)

Re: Recruiting faculty members from SC/ST/OBC communities under Mission Mode

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Caste-based discrimination against people from marginalised caste backgrounds is highly concerning. Our educational institutions are witnessing a rise in such instances. In this regard, in August, the Ministry of Education asked institutions such as IITs, Indian Institutes of Management (IIMs), National Institutes of Technology (NITs) and central universities to fill faculty positions by actively recruiting faculty members from SC/ST/OBC communities under the "Mission Mode" by September 2022. The ministry also sought a monthly report on the actions taken by these institutions to fill the vacant positions. Some IITs brought out notices for the special recruitment drive. But the process is not taking place as actively as it should be. I request the Union Government to take active measures to ensure a speedy recruitment drive in the above-mentioned institutions. The monthly reports should be made publicly available in order to ensure transparency and accountability in the process. A special high-level committee needs to be set up to ensure that the recruitment drive is carried out in accordance with the constitutional principles of reservation.

(ends)

Re: Relief measures for Andhra Pradesh affected by rain and flood related incidents

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): The recent extensive rainfall has caused devastating floods in Kadapa, Chittoor, Anantapur and Nellore districts in Andhra Pradesh in November. Continuous rainfall has inundated 1402 villages and four towns including the Temple city of Tirupati, affecting nearly 1.83 Lakh people in the four districts. As per newspaper reports, rain and flood-related incidents have claimed 41 lives. In terms of damage to infrastructure pertaining to roads and buildings, power, panchayat raj, rural water supply and sanitation, the total loss would run into thousands of crores which is yet to be estimated.

The Central share to the SDRF over the previous years was inadequate to provide the disaster relief measures to mitigate the loss. Further, even the sanctioned amount was not fully transferred. I request the Hon'ble Home Minister through you Sir to sanction substantial interim relief to Andhra Pradesh and depute an Inter Ministerial Central Team to assess the loss.

(ends)

Re: Service conditions of Home guards

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I want to draw the attention of this August House towards the problems of Home guards. Their services are equal to police personnel and casualties are also there throughout the country during police operations but they are getting very meagre wages when compared to other Police forces. They are demanding for regularization of their services for a long time.

During the year 1947, Govt. of India formulated an Act regarding the utilization of the services of the Home Guards. The State Government is paying daily wages to the Home Guards. Recruitment is taking place since 1962. Almost all of them belong to the communities of SCs, STs, BCs and OCs. Their services were mentioned in Home Guard Act as “self voluntary services”. This “self voluntary service” word may be deleted and their services may be regularized and pay and allowances may be sanctioned at par with Police Personnel working in BSF, CRPF, CASF, RAF, RPF, RPSF and Police, Fire, Prohibition, Excise, Forest, Jails, Rta. and also absorbed in the uniform service departments. In Andaman Nikobar, the services of Home Guards were regularized vide IA .No.01/2009 in Civil Appeal No.3379/2009, dated 10-09-2009. The Government of India also regularized the above orders vide Home Ministry letter No.N-U-114040/22/2009, ANL dated 28-1-2015. I request the government to take necessary steps and necessary instructions may be issued to the State Governments on the above demands of Home Guards of the Country.

(ends)

Re: Need to sanction an underpass or subway at Kamarkundu in Arambagh parliamentary constituency, West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): I would like to draw the kind attention of the Government towards Kamarkundu in Arambagh parliamentary constituency, West Bengal. There is an urgent need of underpass for the easy movement of public and the pilgrims who face problems and go barefoot to Tarakeshwar Temple to offer prayers. I urge the Railway Ministry to do a survey for the construction of an underpass or subway in Kamarkundu and sanction it in the interest of the public.

(ends)

Re: Need to fix guaranteed price of cow milk

श्री सदाशिव किसान लोखंडे (शिर्डी): सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी और पूरे महाराष्ट्र राज्य में किसान कृषि के साथ-साथ दुग्ध व्यवसाय के रूप में बड़े पैमाने पर डेयरी व्यवसाय में लगे हुए हैं। विगत कुछ वर्षों से दूध का कारोबार किसानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दूध की कीमत कम और उत्पाद शुल्क में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज एक लीटर दूध के उत्पादन मे 27 रुपए का खर्च आता है तथा वहीं दुग्ध उत्पादक किसान को एक लीटर दूध की कीमत मात्र 18 से 22 रुपए मिलती है तथा शुरूआती दिनों में जहां गाय अच्छी मात्रा में दूध देती है, वहीं कुछ महीनों बाद दूध कम हो जाता है और 6 या 7 वर्ष बाद गाय पूरी तरह से दूध देना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में गो-हत्या पर प्रतिबंध होने की वजह से किसान बांझ गाय को बेच नहीं पाते हैं और साथ ही उसकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

केन्द्र सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस निमित्त किसानों को गन्ना एवं अन्य फसलों की वाजिब कीमत भी दिलाया जाना सुनिश्चित किया हुआ है। यदि गाय दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा।

अत: ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गन्ने एवं अन्य फसलों के लिए गारंटी कीमत किसानों को मुहैया करायी जाती है, उसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक किसानों को भी गाय के दूध के लिए 32 रु0 प्रति लीटर की गारंटीकृत कीमत दिए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

(इति)

Re: Need to look into the root causes of increasing number of cancer patients in the country

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): कैंसर के रोगियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। सभी अस्पतालों में कैंसर रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। यह महामारी से कम नहीं है। देश में कैंसर के इलाज के लिए वैसे ही बहुत कम संस्थान हैं। जहाँ तक अ0भा0आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली का प्रश्न है, वहाँ तो इलाज हो रहा है, किन्तु अन्य भागों में अवस्थित किसी भी एम्स में कैंसर का इलाज नहीं होता है। मात्र टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान एक ऐसा संस्थान है, जहाँ कैंसर का इलाज हो रहा है वह भी सिर्फ पहुँच के रोगियों के लिए, जिनके पास धन की व्यवस्था है। गरीब मरीज तो पैसे के अभाव में जीवन से हाथ धो रहे हैं। कुछ प्राईवेट कैंसर संस्थान हैं, परन्तु वहाँ की फीस और इलाज का खर्च काफी अधिक है, जो कि गरीबों के बस की बात नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 तक करीब 18 लाख कैंसर के नये रोगी हो जायेंगे। सदन में सरकार कह चुकी है कि 70 से अधिक कैंसर संस्थान पूरे देश में खोले जा रहे हैं, मगर उसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है और जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को इस समस्या के जड़ में जाने की आवश्यकता है। देखना चाहिए कि कैंसर एकाएक क्यों बढ़ रहा है? इसके स्थायी उपाय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैंसर में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ताकि समय रहते इस भयावह महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके।

(इति)

Re: Pollution caused by sugar mills in Amroha parliamentary constituency, Uttar Pradesh

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा विभिन्न उद्योगों खास कर चीनी मिलों के कारण होने वाले प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हैं। अमरोहा में 3 चीनी मिलें और एक दूसरी चीनी मिल डिस्टिलरी आदि बना रहे हैं। ये उद्योग भूजल में खतरनाक रासायनिक निर्वहन कर वायु और जल प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ में डायरेक्ट जहरीले रसायन डाल रहे है। सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों और एनजीटी के निर्देशों का अमरोहा और हापुड़ में स्थित इन चीनी मिलों और डिस्टिलरी द्वारा कथित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है, परिणामस्वरूप हर साल हजारों निवासियों की भयंकर बीमारियों से अकाल मृत्यु हो जाती है। आपसे अनुरोध है कि इन उद्योगों द्वारा तथा आसपास के कारखानों द्वारा किए गए उल्लंघन की जांच के लिए एक केंद्रीय टीम मौके पर भेजें ताकि लाखों लोगों के जीवन की सुरक्षा हो सके।

(इति)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، میرا پارلیمانی حلقہ امروہہ مختلف انڈسٹریز خاص کر چینی ملوں کی وجہ سے ہونے والی آلودگی کی وجہ سے بہت متاثر ہے۔ امروہہ میں 3 چینی ملیں اور ایک دوسری چینی مل ڈسٹلری وغیرہ بنا رہے ہیں۔ یہ انڈسٹریزبھوجل میں خطرناک کیمیکل استعمال کرکے ہوا اور پانی میں آلودگی پیدا کر رہے ہیں۔ گنگا اور اس کی مددگار ندیوں میں ڈائریکٹ زہریلے کیمیکل ڈال رہے ہیں۔ سی۔پی۔سی۔بی کے ہدایات اور این۔جی۔ٹی۔ کی ہدایات کا امروہہ اور ہاپوڑ میں مقیم ان چینی ملوں اور ڈسٹِلری دوارہ جان بوجھ کر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کی خطرناک بیماریوں سے اموات ہو رہی ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان انڈسٹریز سے اور آس پاس کے کارخانوں کے ذریعہ کی گئی خلاف ورزی کی جانچ کے لئے ایک مرکزی ٹیم موقع پر بھیجیں تاکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔

شکریہ

Re: Affordable medical treatment for Spinal Muscular Atrophy disorder

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a genetic disorder characterized by weakness and wasting Atrophy in muscles used for movement Skeletal muscles. It is caused by loss of specialized nerve cells. SMA mostly affects small babies and children at very early age. Babies with severe SMA type 1 do not live beyond to 1 or 2 years, Type 2 & 3 live up to teenage and adulthood. However, they are confined to wheelchair and go through Scoliosis of spine, poor lung functions about 625 patients exist in India. There are three life saving medicines approved for SMA by US FDA. However none of them are yet available in India.

However a reimbursement pathway would be needed for this.

I request the honourable minister to intervene to arrange access and affordability of treatment and cure for muscular Atrophy, Rare life threatening Neuro Muscular genetic Disorder &also make this medicine available in India so that all the SMA patients get a chance to live.

(ends)

Re: Redressal of grievances of opium poppy crop growers of Rajasthan

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): आपके माध्यम से राजस्थान के भीलवाड़ा व चितौड़गढ़,उदयपुर सहित मेवाड़ क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों की समस्या व मांगो की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों की मंशा के अनुरूप मार्फिन के नियम को हटाया जाए क्योंकि इस नियम के हटने से ही किसानों को बराबर बारी में पट्टे मिलेंगे,साथ ही जिस डोडे का सरकार खेतो में डिस्पोजल करवाती है उसका मुवावजा किसानों को दिया जाये व दवाई आदि में काम आने वाले अफीम के उत्पाद कोडिन फॉस्फेट का विदेश से आयात बंद करके उसे भारत मे ही अत्याधुनिक मशीनें लगाकर इसके उत्पाद बनाये जाए ताकि अफीम उत्पादक किसानों को सही भाव मिल सके साथ ही 1998 के बाद जिन किसानों के अफीम के पट्टे निरस्त किये गए हैं, उन्हें वापिस पट्टे देकर और नए पट्टे मेवाड़ क्षेत्र के किसानों को दिए जाएं व अफीम तोल का परिणाम तुरन्त किसानों को वहीं देना चाहिए जहां तोल किया जाता है।

(इति)

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY (REGULATION) BILL

1438 hours

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : अब सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 पर चर्चा करेंगे।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Hon. Chairperson, Sir, I rise to move:

> "That the Bill for the regulation and supervision of the assisted reproductive technology clinics and the assisted reproductive technology banks, prevention of misuse, safe and ethical practice of assisted reproductive technology services and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

सभापति महोदय, यह एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पहले 14 सितम्बर, 2020 को पार्लियामेंट में आया था और लोक सभा ने उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था। स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विस्तार से विचार किया। विचार करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कई सुझाव आए हैं, उन सुझावों को भी हमने ध्यान में लिया है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? फीमेल से ओवम लेकर, मेल के स्पर्म से लेबोरेटरी में एम्ब्रियो डेवलप करके, उसे फिर से फीमेल में इम्प्लांट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस बिल के कई पहलू हैं और इसे लाने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि देश में आज के दिन में कई ऐसी क्लीनिक्स चल रही हैं, जो आईवीएफ कर रही हैं। उनको रेगुलेट करना था और रेगुलेट करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि इसमें कई ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जिनमें ओवेरियन स्टिमुलेशन करने के लिए इंजेक्शन भी देना होता है, जिससे उस महिला के हेल्थ पर भी इफेक्ट हो सकता है। उसमें एग रिट्राइवल की प्रोसेस भी होती है, आईवीएएफ और इंट्रा-यूटराइन इनसेमिनेशन की सारी प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस होती है और एम्ब्रियो रखने के लिए बैंकिंग की व्यवस्था होती है। इस सारी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, मैं यह बिल इस सम्माननीय सदन में ला रहा हूं। सदन इसके ऊपर विचार करे और इसे पारित करे।… (व्यवधान) (इति)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill for the regulation and supervision of the assisted reproductive technology clinics and the assisted reproductive technology banks, prevention of misuse, safe and ethical practice of assisted reproductive technology services and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

(1440/SNT/SPS)

1440 hours

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Respected Chairman, Sir, it is quite heartening to finally debate a Bill in this House. It has been a long time since we have had the opportunity to debate a Bill. I would like to first thank my Party President, Mrs. Sonia Gandhi, for giving me the opportunity to be the first speaker to speak on a Bill in this Session.

While we have over a billion people in India and we always consider India to be an overpopulated country, there are many people who are unable to have children and who find the benefit from assisted reproductive technologies. So, it is essential that this technology is available to all, it is regulated also, and it may be ensured that best medical practices are followed while this technology is made available to all.

Sir, indulge me a little bit. I am a great admirer of our *puranas*, *ithigaasams* and epics. I grew up reading Amar Chitra Katha. I do not even know whether Amar Chitra Katha is still around or not but I grew up reading Amar Chitra Katha. When I was growing up, my maternal grandmother told me many fables and stories. This is a Government which professes to draw inspiration from our *puranas*, from our *ithigaasams*, and from our epics. Government Ministers have spoken about *pushpak viman*. Even research has been done on the existence of *pushpak viman* and on the science behind it. The Prime Minister has alluded to Ganesha when he was addressing a conference of doctors in 2014. I come from Sivaganga. Pillaiyarpatti is the biggest and the most famous temple over there, and we are all great devotees of Ganesha. In fact, there is not a single day that goes by where I do not say:

"एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।"

The Prime Minister, when he spoke to the doctors said that evidence of plastic surgery was there because Ganesha has an elephant head. The head was fitted to a human being. It is a different matter but I have always wondered how an elephant head of that circumference can be fitted to a human. But still, we draw inspiration from our *puranas*. Our epics have so many instances of unconventional births. *The Mahabharata* is the starting point of that. If you look at the Kuru Dynasty of the Kauravas, Dhritarashtra and Gandhari could not have children. Duryodhana was also known by the name of Suyodhana. In fact, we

must have a debate on why Duryodhana is not called as Suyodhana. His real name is Suyodhana. Somebody must explain this to me at some point in time. In fact, the legend is that all the Kuru princes, the hundred of them were born in earthen pots. We always believe that this is the beginning of the test tube baby. It perhaps came from this inspiration. This is what your Government believes. Your Government always draws inspiration from epics.

Similarly, in the case of Pandavas, you know that King Pandu was cursed by Durvasa. He could not have children through Kunti or Madri. In fact, Kunti had to invoke the Gods to have children. That system was called Niyoga. Surya was the father of Karna; Dharma was fathered by Yama; Arjuna was fathered by Indra; Bhima was fathered by Vayu; and Nakula and Sehdev were fathered by Ashwini. So, the system of Niyoga was there in those days.

In Kerala, the most revered God, Ayyappa is said to have been born by the union of Shiva and Vishnu. That is why he is called Hari Hara Suta. In Tamil Nadu, the most revered God is Murugan. In fact, my parents have named me after the same God. Karti is one more name for Murugan. He was born from the *netrikan*, which is the third eye of Shiva. So, unconventional births are mentioned in our *puranas* throughout.

This Government always says it draws inspiration from these *puranas*. But this law which they have drafted is not inspired by the liberal Hindu epics. In fact, this law has been drafted by somebody who has got a regressive, colonial, and Victorian mindset. This law has not come from the Hindu liberal traditions. This law has come from the completely regressive, Victorian, and colonial mindset. I will tell you why. This law excludes many people, rather than it includes. When I have given you so many instances of unconventional births and unconventional unions in our Hindu epics, this law only allows married people to have access to this technology. It does not allow LGBTQ people to have access to this technology. It does not allow single men to have access to this technology. So, this law is actually a Victorian law; it is not a Hindu law.

(1445/RBN/RAJ)

So, do not ever say that you are a Government which is actually propagating Hindu values. The Hindu values are liberal values. You are, in fact, propagating a Victorian colonial value. … (*Interruptions*) I do not know Hindi. I did not know Hindi earlier and I do not know Hindi even now.

This law does not take into account the new realities of India. Of course, these new realities are not new realities. These were there in our ancient scriptures. Those unions which were always there, were suppressed by the colonial mentality. These unions must also be given access to this technology. The LGBTQ population, live-in couples, and single men must also have access to this technology if they want so.

This law is discriminatory. This law violates article 14 of the Constitution as well as the Puttaswamy judgement of the hon. Supreme Court. The liberty of procreation and choice of family life are an intrinsic aspect of the fundamental right to privacy. Every individual who is mentally and physically fit to be a parent and also financially fit, must be able to avail these technologies and you cannot discriminate people by the lifestyle choices they make and deny them access to this technology.

This law again is patriarchal. That is again a hallmark of this Government and the hallmark of all it says. A person who is capable of donating an egg, has to be married and has to have a child who is at least three years old; only then can she become a donor. A single woman cannot be a donor. Again, this reeks of patriarchy. According to this Government, unless a woman fulfils the role of becoming a mother in an established union, she cannot become a donor. This is again shameful. You again take away the right of an individual to decide to be a donor or not. This aspect has to be looked into. The Minister needs to address this issue. He should definitely give an answer on why only married women and that too who have a child and whose child has to be three years old, can become a donor of the egg.

There is something which is very troubling in this law. This law says that you can send the embryo for determining any pre-existing deficiencies. This is very problematic because you are not defining what these pre-existing heritable life-threatening genetic diseases are. This almost borders on eugenics, where you want to do selection, where you want to decide what kind of children can be born and what kind of children cannot be born. So, the Minister must definitely address this issue. He should address as to why these specific diseases which they want to prevent have not been defined and leaving a very gaping hole there.

The Surrogacy Bill was passed in this House without a debate. That Bill is still pending in the Rajya Sabha. So, it has not yet become a law. But this Bill

says that there is going to be an Oversight Board which will draw its powers from the Surrogacy Act. Why are you bringing this Bill when that Bill has not become a law?

There are many conflicts between these two laws. Why do you need to have two Bills? Why could both not be combined? The Surrogacy Bill says that you must keep record of 25 years. This Bill says you must keep the record for ten years. Again, the Oversight Board will draw its powers from the Surrogacy Act. The Surrogacy Bill has not become an Act yet. So, how are you going to establish the Board where you are drawing the powers from that Act which is not there? So, there is a lot of conflict. The Minister must address as to why there is a haste in bringing this Bill when that Bill has not been passed? And why is there a need to have two separate Bills, instead of having one combined Bill, which deal with pretty much the same subject?

Another issue has not been addressed. It could be problematic. It is a very sensitive issue. A child born through a donor, after the age of 18, might be curious to find out who the father is. That right is not given here. I accept that there is a privacy right of the donor. There must be some sensitivity in this. The ICMR has suggested that the characteristics of the donor must be revealed to the child. The identity, of course, cannot be given because most donors are anonymous. So, that sensitivity has not been handled in this Bill. The Minister must inform us how he is going to handle this sensitive issue. As I said, it is a very sensitive subject. I accept that. There is no politics in it. It is a very sensitive subject and he must deal with it.

As far as complaint mechanism goes, only the Board can complain. An individual cannot complain. So, you are really taking away the fundamental right of a person from going to court. Only the Board can go to court and not the individual. Again, this is very problematic. You cannot take away the fundamental right of a person to go to court. The Board is only established by the Surrogacy Act and the Surrogacy Act has still not been established. So, that is another lacuna which you must address.

(1450/SRG/VB)

You want the Aadhaar card for the donor because you want to identify the donor through that Aadhaar card. But the donor has to be anonymous. What if there is a leak of data? What are we doing to protect that because a lot of people

are donors, but you do not want their identities to be there? It is because they have no legal right over the child. So, lots of issues of privacy, lots of issues of fundamental rights and lots of issues of discrimination are very much there and we must take them into account.

The clinics are not regulated. They are becoming commercial establishments. The Minister knows that. IVF is a very, very expensive procedure. People go through many cycles before they have any success in it. It is a very expensive procedure. There is no control over its pricing. There is no control over how these clinics are established. But you prohibit the donors from charging anything because you do not want commercial exploitation of that. There is a lot of merit in that, but there must be some balance. While you are not regulating the medical practice, you are completely regulating the surrogacy part of it. So, there must be some balance between them and there must be some clarity in it.

The other thing that has not been addressed is this. This is a very expensive procedure. Many people from all strata of society want to have children of their own. What is the provision for them who do not have money? Is there any programme which the Government is proposing by which people who do not have the resources can also access this technology? This technology cannot be available only to the rich. This technology must be available to everybody who wants to have children. It should be accessible to all. So, the Government must definitely address this issue as well.

As I said in the beginning, this is the Government which always says that it draws inspiration from our *puranas*. But this Government is not at all acting in the way in which I have been taught Hindutva by my grandmother. This Government is a Victorian colonial Government and it acts like that. Every act of this Government is colonial. This Bill is also a colonial Bill and not a Bill which is true to our faith, which is liberal, which accommodates everybody, looks at different kinds of relationships, and looks at all kinds of things encompassing all philosophies. That all-encompassing philosophy has always been lacking in this Government. This Bill is yet another example of that. Thank you very much.

(ends)

1452 hours

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I rise to support the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020. In India, assisted reproductive technology has remained unregularized for a long, long time.

Baby Manji Yamada Versus Union of India was the first case wherein the Supreme Court had remarked on the importance of developing a strong legislative framework to govern surrogacy which is a common method of assisted reproductive technology in India. This judgement also holds critical importance because it was decided upon by the judges under the presumption of legality of surrogacy agreements and surrogate motherhood. This judgement also acts as the precursor to the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha in August, 2019 after which it was referred to the Select Committee.

The Surrogacy (Regulation) Bill bans commercial surrogacy. However, it has allowed altruistic surrogacy to the intending infertile Indian married couples between the age of 23-50 years for females and 26-55 years for males. The reason why we need regulation of the assisted reproductive technology is that lots of studies have been done in this field. Since 2002, studies have reported that India has boomed as a major centre for assisted reproductive technology, especially surrogacy. A report by the Confederation of Indian Industry in as early as 2002 estimated that the practice will generate about two billion dollars to three billion dollars per year till 2012.

The 129th report of the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the Assisted Reproductive Technology Bill, 2020 had also highlighted the growing market for assisted reproductive technology facilities and a growing demand for the same. A market research by Fortune Business Insights on assisted reproductive technology has found that the high prevalence of infertility among citizens is responsible for the booming market for assisted reproductive technology.

A report by the Ministry of Women and Child Development also emphasized that there has been an increase in the number of foreign couples coming to India who opt to travel to India to have surrogate children. There can be lots of reasons behind that. One reason is that there is a legislative prohibition in some of the countries. That is one of the reasons why foreign couples come

to India. One of the most important reasons why foreign couples come to India is that earlier there was a lack of any legislation which was having regulation over assisted reproductive technology. The second reason is that the cost of assisted reproductive technology in India was much, much lower than in other parts of the world.

(1455/AK/PC)

The increasing influx of foreigners to India for the Assisted Reproductive Technology procedures has been one of the key reasons for medical tourism in India. The heightened financial disability among women -- of a particular section of the society -- in India has been an important factor that aids these practices. The prospect of earning money in exchange of providing support for the Assisted Reproductive Technology procedures has made many women in India an easy target for rich and wealthy couples who want to have children through Assisted Reproductive Technology.

This has paved way for ‘Womb on rent’ as a concept of earning livelihood for the destitute women with no financial resources to back them. So far, we have seen that mostly the under-privileged women come forward for giving services or helping in Assisted Reproductive Technology, particularly for becoming surrogate mothers. This, in turn, leads to a lot of exploitation of women, abandonment of children, and there is commercialisation seen in this field.

Initially, Assisted Reproductive Technology came on a humanitarian ground to assist those couples who are infertile and who cannot have their own children. But, unfortunately, over a period of time, a lot of commercialization has taken place. Hence, we need the regulation of Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill.

This Assisted Reproductive Technology Bill addresses an array of issues that have been observed in practices prevailing in India. The Bill provides for eligibility criteria for couples who want to avail the benefits of Assisted Reproductive Technology, and eligibility criteria for those who are rendering services related to Assisted Reproductive Technology. It also mandates proper registration of Assisted Reproductive Technology clinics and banks to enhance scrutiny of their functioning by authorities constituted by the Government under this Act.

As regards the objectives of the Bill, it seeks to regulate Assisted Reproductive Technology services including the In-Vitro Fertilisation, egg retrieval, embryo transfer, and surrogacy among many other Assisted Reproductive Technologies. Firstly, the Bill was drafted with an objective for regularizing the registration of the Assisted Reproductive Technology clinics and banks; secondly, regularising the age and other criteria for couples who are looking to avail for the benefits of Assisted Reproductive Technology; thirdly, specifying the number of embryos to be planted to the uterus of a woman; fourthly, disallowing sex selection at every stage of the Assisted Reproductive Technology process; and fifthly, ensuring penal provisions for unethical practices in the Assisted Reproductive Technology clinics.

How is registration going to benefit us? I would like to share a data with this august House. As of 2017, only 20 per cent of the IVF clinics and two per cent of the functional Assisted Reproductive Technology clinics were registered under ICMR. This means that 80 per cent of the IVF clinics were not registered and 98 per cent of the Assisted Reproductive Technology clinics were not registered. This indirectly means that we had no control over what was happening. They were not accountable if any mishap happened there because they were not registered. So, lots of these issues were coming up and that is why this registration is of prime importance to all of us.

A centralised registry of the Assisted Reproductive Technology clinics is the first step towards ensuring transparency in the service that they are providing. This point is very important. Anything in Assisted Reproductive Technology has to be transparent. Unfortunately, in the past, we have seen that not many things were happening in a transparent manner. Hence, transparency will come once there is a national registry for registering Assisted Reproductive Technology clinics in the country. This will also help in ensuring legitimacy in their clientele and regularise the cost at which these services are being provided. This will also allow the Government to monitor the quality of services that are being provided by these entities, which is critical to ensure the health safety of mother and child who are involved in the Assisted Reproductive Technology process. Registration will also further ensure strict adherence to the guidelines issued by the Government including submission of the documents and proof of manpower who are trained for these complex procedures.

When we talk of Assisted Reproductive Technology, it is a very complex procedure, and we need to have skilled manpower working in those Assisted Reproductive Technology clinics.